

DAILY **CURRENT AFFAIRS**

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 11-06-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday 11 June, 2025

Editin : Internatinal Table f Cntents

Page 01 Syllabus : GS 1 : Indian Sciety	भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ हुई: यूएनएफपीए
Page 01 Syllabus : GS 3 : Disaster Management	केरल तट पर जलता हुआ, सूची में शामिल कंटेनर जहाज़; तेल रिसाव के लिए अलर्ट जारी
Page 08 Syllabus : GS 1 : Indian Sciety	अधिकतम मुंबई: शहर को अपनी परिवहन आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है
Page 08 Syllabus : GS 2 : Internatinal relatins	भारत-पाकिस्तान मुद्दों पर वैश्विक होने के खतरे
Page 10 Syllabus : GS 3 : Indian Ecnmy & Security	FSDC साइबर सुरक्षा बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने पर विचार कर रहा है
Page 08 : Editrial Analysis: Syllabus : GS 2 : Gvernance	भारत का कानूनी पुल पारस्परिकता का है, बाधाओं का नहीं

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में जनसंख्या अनुमान, प्रजनन दर और आयु संरचना सहित प्रमुख जनसांख्यिकीय रुझानों पर प्रकाश डाला गया है।

India's population hits 146.39 crore: UNFPA

The country's total fertility rate declined to 1.9, falling below the replacement level of 2.1, it says

The number of people in India expected to peak at 170 crore before declining in around 40 years

It says 68% of the population in the world's most populous nation is in the age group of 15 to 64

The Hindu Bureau
NEW DELHI

India's population is estimated to have reached 146.39 crore by April, says a new UN demographic report, which adds that the country's total fertility rate (TFR) has declined to 1.9, falling below the replacement level of 2.1.

The population is expected to grow to 170 crore before starting to dip in about 40 years, the report titled "State of the World Population 2025: The Real Fertility Crisis" says. It calls India the "world's most populous nation", while pegging China's current population at 141.61 crore.

The demographic indicators in the United Na-

tions Population Fund report for 2025 are close to India's own projection of its population published in 2019 by a technical group of experts. According to these projections, India, as of 2025, will have a population of 141.10 crore.

The decennial Census, due to have been conducted in 2021, has been delayed and the government has now announced that it will be completed by March 2027.

The last Census was conducted in 2011.

Replacement level TFR
According to the latest Sample Registration System statistical report published by the Office of the Registrar General of India for 2021, the TFR in India

Below replacement

Indian women are having fewer children than needed to maintain the population size across generations



Source: UNFPA data for 2025

was 2.0, the same as the year before, with the report saying that the replacement level TFR "has been attained" nationally.

The TFR measures the number of children a woman is expected to have throughout her reproductive age.

Replacement level TFR is the rate needed for each generation to replace the previous generation's population.

The real crisis

The UN report says that millions of people are not able to realise their real fertility goals.

Calling this the "real" crisis, and not overpopulation or underpopulation, the report calls for the pursuit of reproductive agency – a person's ability to make free and informed choices about sex, contraception and starting a family – in a changing world.

India's youth population remains significant, with about 24% of the population in the age bracket of 0-14, 17% in the age bracket of 10-19, and 26% in the age group of 10-24. Further, the report estimates that 68% of the population in India is of working age (15-64 years).

Elderly population

The elderly population (65 and older) currently stands at 7%, a figure that is expected to rise in the coming decades as life expectancy improves, the report adds, confirming the projections the government in India has been working with.

The UN report says that as of 2025, life expectancy at birth is projected to be 71

years for men and 74 years for women.

The report says its statistical tables on demographic indicators "draw on nationally representative household surveys" such as "Demographic and Health Surveys (DHS) Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), United Nations organizations estimates, and inter-agency estimates".

"They also include the latest population estimates and projections from World Population Prospects: The 2024 revision, and Model-based Estimates and Projections of Family Planning Indicators 2024 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division)," it adds.

मुख्य बातें:

• भारत की वर्तमान जनसंख्या स्थिति:

- अनुमान है कि अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ तक पहुँच जाएगी, जो चीन (141.61 करोड़) से आगे निकल जाएगी, जिससे भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
- अनुमान है कि जनसंख्या में गिरावट शुरू होने से पहले लगभग 40 वर्षों में यह 170 करोड़ के शिखर पर पहुँच जाएगी।

• कुल प्रजनन दर (TFR):

- भारत की TFR घटकर 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
- यह पुष्टि करता है कि भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल कर लिया है, जैसा कि 2021 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है।

• जनसांख्यिकीय लाभांश:

- जनसंख्या का 68% हिस्सा 15-64 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में है, जो संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश को दर्शाता है।

- युवा आबादी मजबूत बनी हुई है, जिसमें **0-14** आयु वर्ग के **24%**, **10-19** आयु वर्ग के **17%** और **10-24** आयु वर्ग के **26%** लोग हैं, जो शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं।
- **बुजुर्ग आबादी के रुझान:**
 - बुजुर्ग आबादी (**65+** वर्ष) वर्तमान में **7%** है, लेकिन आने वाले दशकों में जीवन प्रत्याशा में सुधार (पुरुषों के लिए **71** वर्ष, महिलाओं के लिए **74** वर्ष) के कारण इसके बढ़ने की उम्मीद है।
 - इससे वृद्धावस्था से संबंधित नीतिगत चुनौतियाँ पैदा होंगी, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा की उच्च लागत और सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरतें।
- **"वास्तविक" प्रजनन संकट - प्रजनन एजेंसी:**
 - **UNFPA** रिपोर्ट ने अधिक जनसंख्या से ध्यान हटाकर अप्राप्य प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है।
 - इसमें प्रजनन एजेंसी को प्रसव, गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन के संबंध में सूचित विकल्प बनाने की क्षमता को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- नीति पुनर्समायोजन: प्रतिस्थापन से नीचे की टीएफआर के लिए जनसंख्या नीति में बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें वृद्धि को नियंत्रित करने से लेकर वृद्धावस्था को प्रबंधित करने और प्रजनन अधिकारों का समर्थन करने तक शामिल है।
- अवसर की जनसांख्यिकी खिड़की: बड़ी कामकाजी आयु वाली आबादी मानव पूंजी में निवेश के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सीमित जनसांख्यिकीय खिड़की प्रदान करती है।
- स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचना: बढ़ती जीवन प्रत्याशा और वृद्धावस्था के रुझान वृद्धावस्था देखभाल, पेंशन प्रणाली और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- जनगणना और डेटा अंतराल: भारत की **2021** की जनगणना (अब **2027** तक अपेक्षित) में देरी ने डेटा अंतराल पैदा कर दिया है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से योजना बनाना और लागू करना कठिन हो गया है।

निष्कर्ष:

- भारत की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च वृद्धि से स्थिरीकरण और अंततः गिरावट की ओर एक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर रही है। इस बदलाव के लिए रणनीतिक जनसांख्यिकीय योजना की आवश्यकता है, जिसमें प्रजनन स्वायत्तता, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा सुधार और बुजुर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। चुनौती संख्या में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि प्रत्येक नागरिक सम्मान, अवसर और विकल्प के साथ जीवन जिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत की घटती कुल प्रजनन दर (TFR) और बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी अवसर और चुनौतियाँ दोनों पेश करती है। भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास पर इन जनसांख्यिकीय रुझानों के प्रभावों पर चर्चा करें और उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाएँ। (250 wrds)

Page 01 : GS 3 : Disaster Management:

सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर जहाज एम.वी. वान हाई 503 में केरल तट से करीब 88 समुद्री मील दूर आग लग गई। इस घटना ने गंभीर पर्यावरणीय, सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिसके कारण भारतीय एजेंसियों द्वारा समन्वित अग्निशमन और रिसाव प्रतिक्रिया अभियान शुरू किए गए हैं।

मुख्य मुद्दे और घटनाक्रम:

• जहाज पर आग और विस्फोट:

- कथित तौर पर कोलंबो से मुंबई जाते समय जहाज पर कंटेनर विस्फोट के बाद आग लगी।
- जहाज पानी में डूबा हुआ है, कंटेनर पानी में गिरे हुए हैं और **10-15** डिग्री का झुकाव दिखाई दे रहा है, जो संरचनात्मक समझौते का संकेत देता है।

• खतरनाक माल:

- जहाज पर **157** कंटेनर थे, जिनमें खतरनाक सामग्री थी - जिसमें ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ और जहरीले रसायन शामिल थे - जो मानव और समुद्री जीवन दोनों के लिए उच्च जोखिम पैदा कर रहे थे।
- आग वाले क्षेत्र के पास **2,000** टन ईंधन तेल और **240** टन डीजल की मौजूदगी विनाशकारी तेल रिसाव या विस्फोट का खतरा पैदा करती है।

• पर्यावरणीय जोखिम:

- **INCIS** द्वारा संभावित तेल रिसाव की चेतावनी जारी की गई है।
- केरल तटरेखा पर, विशेष रूप से कोझीकोड और कोच्चि के बीच, बहते हुए कंटेनर फंस सकते हैं, जिससे समुद्री और तटीय प्रदूषण हो सकता है।
- **INCIS** ने मलबे और खतरनाक सामग्री की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए बहाव सिमुलेशन उपकरण और खोज-बचाव प्रणाली तैनात की है।

• प्रतिक्रिया और समन्वय:

- भारतीय तटरक्षक जहाज - समुद्र प्रहरी, सचेत और समर्थ - अग्निशमन और सीमा शीतलन कार्यों में लगे हुए हैं।
- हवाई निगरानी की गई है, और कोझीकोड के जिला कलेक्टर द्वारा एक जिला-स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया दल को सक्रिय किया गया है।

Burning, listing container ship adrift off Kerala coast; alert sounded for oil spill

The Hindu Bureau
KOZHIKODE

Authorities issued a potential oil spill advisory on Tuesday even as explosions and a massive fire rocked the M.V. Wan Hai 503, a Singapore-flagged vessel that caught fire nearly 88 nautical miles off the Kerala coast near Kozhikode on Monday. Efforts to control the fire were still continuing through Tuesday and four crew members are still reported missing, while six others have been admitted to hospital.

The ship was en route from Colombo to Mumbai when fire broke out on board after a container explosion. The vessel is currently adrift and the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) has issued advisories warning of drifting containers and a potential oil spill.

According to its cargo manifest, the ship is carrying 157 containers with hazardous substances – including flammable liquids and solids, solids that can spontaneously combust and substances harmful to human health – due to which firefighting operations require caution and expert advice.

Inflammable materials

There are also approximately 2,000 tonnes of fuel oil and 240 tonnes of diesel in tanks located adjacent to the fire zone on the ship, creating an imminent threat of explosion.

Flames were reported from the mid-ship area and container bay just ahead of the accommodation block. Though the forward bay fire has been brought under control, thick smoke is reportedly rising from the vessel.

The ship is tilting approximately 10 to 15 de-



Coast Guard ships Samudra Prahar and Sachet working to douse the fire on M.V. Wan Hai 503 on Tuesday. X/@INDIACOASTGUARD

Vessel has 157 containers with hazardous materials

The Hindu Bureau
KOZHIKODE

According to the cargo manifest, there are 157 containers with hazardous substances on M.V. Wan Hai 503. These include flammable liquids (Class

3); flammable solids (Class 4.1); spontaneously combustible solids (Class 4.2); and toxic substances (Class 6.1) harmful to human health.

SMOKE IN THE SEA
» PAGE 3

grees to its left, and a number of containers have reportedly fallen overboard, with 10-15 of them spotted adrift on a course toward the Kerala coast. Coast Guard ships *Samudra Prahar* and *Sachet* are carrying out firefighting and boundary cooling operations at sea. Another Coast Guard vessel *Samarth*, with a team of salvors is being deployed from Kochi to support the ongoing efforts. A Coast Guard Dornier aircraft also conducted an aerial survey of the site.

INCOIS has activated its Search and Rescue Aid Tool to track the possible drift patterns of containers, debris, or people who may have gone overboard.

Simulations show that the containers are likely to continue to drift in the ocean for the next three days and might take longer to reach the beach. Howev-

er, caution is advised about a few containers beaching between Kozhikode and Kochi. The situation is being closely monitored and updated drift directions will be provided, the INCOIS statement said.

Close watch

Kozhikode District Collector Snehil Kumar Singh directed the district-level pollution response team to make arrangements to address a possible spill of fuel in the sea or the shore, and the resulting pollution impacts.

A doctor at the Hospital where the crew members have been admitted said that the crew members had not jumped into the water as had been reported earlier. They were all in the vessel and were rescued from their lifeboat by the Coast Guard. (With inputs from the Mangaluru Bureau)

- अस्पताल में भर्ती चालक दल को लाइफबोट से बचाया गया, जो पहले की धारणाओं के विपरीत है कि वे समुद्र में कूद गए थे।

परिणाम और चिंताएँ:

- पर्यावरणीय आपदा जोखिम:

- यदि ईंधन टैंक फट जाते हैं या खतरनाक माल फैल जाता है, तो इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, मत्स्य पालन में व्यवधान और तटीय स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं।

- समुद्री खतरे की तैयारी में खामियाँ:

- यह घटना भारतीय जलक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर रासायनिक कंटेनरों की हैंडलिंग और आग बुझाने सहित मजबूत समुद्री आपदा प्रोटोकॉल की आवश्यकता को उजागर करती है।

- सुरक्षा और निगरानी:

- बहते हुए जहाज और कंटेनर निरंतर समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) और अंतर-एजेंसी समन्वय के महत्व पर जोर देते हैं।
- भविष्य में आपातकालीन मानचित्रण और अलर्ट के लिए **INCIS** के बहाव ट्रेकिंग सिस्टम जैसे वास्तविक समय के उपकरणों को मजबूत किया जाना चाहिए।

- कानूनी और नियामक निरीक्षण:

- यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कानूनों के तहत देयता का आह्वान कर सकता है, और भारतीय समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले खतरनाक कार्गो की बेहतर जांच और विनियमन की मांग कर सकता है।

निष्कर्ष:

- वान हाई 503 आग आधुनिक कंटेनर शिपिंग से जुड़े बहुआयामी जोखिमों की एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है - मानव जीवन, समुद्री पारिस्थितिकी और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरों को जोड़ती है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए भारत के आपदा प्रतिक्रिया बुनियादी ढांचे, तेल रिसाव की तैयारी और तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। इसके अलावा, खतरनाक कार्गो विनियमन और समुद्री सुरक्षा मानकों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वान हाई 503 आग की घटना भारत की समुद्री आपदा तैयारियों की कमजोरियों को उजागर करती है। तटीय आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और तेल रिसाव प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। (250 wrds)

मुंब्रा में हाल ही में हुई त्रासदी, जिसमें मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ और असुरक्षित यात्रा के कारण चार लोगों की मौत हो गई, ने एक बार फिर भारत की वित्तीय राजधानी में शहरी परिवहन की संरचनात्मक समस्याओं को उजागर किया है। रेलवे ने स्लाइडिंग दरवाज़े और बेहतर वेंटिलेशन के प्रस्ताव के साथ जवाब दिया है, लेकिन अंतर्निहित संकट को दूर करने के लिए गहरे, दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है।

मुख्य मुद्दे उजागर हुए:

• अत्यधिक भीड़ और असुरक्षित रेल यात्रा:

- मुंबई की उपनगरीय ट्रेनें प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं, फिर भी बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा प्रणालियाँ पुरानी बनी हुई हैं।
- 2017 के एलफिंस्टन भगदड़ जैसी घटनाएँ और ट्रैक-क्रॉसिंग से होने वाली लगातार मौतें सिस्टम पर पुराने तनाव को दर्शाती हैं।
- स्लाइडिंग दरवाज़े, वेस्टिबुल और भीड़ प्रबंधन कर्मचारियों जैसे प्रस्तावित हस्तक्षेप तत्काल जोखिमों को कम कर सकते हैं, लेकिन परिवहन के एक ही तरीके पर अत्यधिक निर्भरता के मूल मुद्दे को हल नहीं करते हैं।

• शहरी परिवहन असमानता:

- शहरी गरीबों और कामकाजी वर्ग के लिए ट्रेनें परिवहन का सबसे सस्ता साधन बनी हुई हैं।
- मेट्रो और निजी वाहन जैसे विकल्प अक्सर महंगे या दुर्गम होते हैं।
- बस सेवाएँ और अंतिम मील कनेक्टिविटी अपर्याप्त और कम उपयोग की जाती है।

• बुनियादी ढाँचा असंतुलन:

- जबकि सड़कें और वाहनों की आवाजाही में सुधार हुआ है, उपनगरीय रेलवे प्रणाली दशकों से काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है।
- मुंबई का शहरी विस्तार उत्तर-दक्षिण गलियारे का अनुसरण करता है, जिससे प्रमुख परिवहन धमनियाँ ओवरलोड हो रही हैं।
- शहर की योजना ने क्षेत्रों में बहुविध एकीकरण और न्यायसंगत विकास को नजरअंदाज कर दिया है।

Maximum Mumbai

The city needs long-term solutions to its transportation needs

The railways have proposed automatic sliding doors with ventilation louvers in all Mumbai suburban trains by next year in response to the Mumbai train tragedy on Monday – four people died and nearly a dozen others were injured. Sliding doors could potentially force people inside and prevent footboard travel, a factor in the accident. They could ensure that passengers do not get down at unscheduled stops and put themselves in danger of being mowed down by passing trains. The proposed vestibules connecting the coaches may also help to evenly distribute the crowds. As in Japan, each station may then need a few enforcers who could shove the crowds in so that the doors could shut and the trains move. While footboard travel is indeed a dangerous safety issue, it is only an outcome of the dangerous overcrowding in Mumbai trains. For vast numbers of people, the trains offer the least expensive travel option. Not too long ago, the dangers of overcrowding resulted in the infamous stampede at the Elphinstone Road station bridge in 2017. Multiple deaths are common along the three arteries that are the lifelines of Mumbai – the Central, Harbour and Western railway lines. Many are hit by trains while crossing tracks instead of using roads or bridges. While rail safety is an immediate issue that needs to be addressed, it is also time city leaders engineer inexpensive, alternative travel options to the trains.

Mumbai's trains have been seen as an inevitable part of the extreme urbanisation that the city represents and romanticised by literature. But they are simply not humane modes of transport. The suburban train system has undergone little change over the decades though the city has boosted its roads and enabled more vehicular traffic. Two-wheelers that were a rarity a few decades ago are now common. While the Metro promises to decongest the city to an extent, these services price out the lower classes. Bus services could be enhanced for routes connecting shorter distances. Along with doubling efforts to change the structuring of the city from a north-south network with commuter movements dictated by times, planners should consider expanding ferry transport – a cheaper and possibly more eco-friendly mode of transport to a city bound by the sea. Broadly speaking though, stampedes such as the one in Bengaluru, fire accidents in congested areas, and train tragedies such as the Mumbai one only highlight how unprepared India is to handle the consequences of urbanisation and the thrust to overturn the engagement of the vast majority of the people with agriculture.

- **छूटे हुए अवसर:**

- मुंबई एक तटीय शहर होने के बावजूद, फेरी सेवाएँ काफी हद तक अविकसित हैं।
- छोटी दूरी की बस मार्ग और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के साधन नियोजन प्राथमिकताओं में गौण बने हुए हैं।

व्यापक निहितार्थ:

- **बिना तैयारी के शहरीकरण:**

- यह घटना न केवल मुंबई में बल्कि पूरे भारत में अनियमित शहरीकरण के परिणामस्वरूप बुनियादी ढाँचे पर तनाव को दर्शाती है।
- बेंगलुरु में भगदड़ और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शहरी आग जैसी इसी तरह की घटनाएँ शहरी नियोजन में प्रणालीगत खामियों की ओर इशारा करती हैं।

- **कृषि और ग्रामीण विकास की उपेक्षा:**

- शहरों की ओर पलायन आंशिक रूप से ग्रामीण/कृषि आजीविका में आर्थिक गिरावट के कारण है।
- भारत का शहरी विकास इसकी नियोजन क्षमता से कहीं आगे निकल रहा है, जिससे शहरी मलिन बस्तियों और अनौपचारिक क्षेत्रों में रहने लायक स्थिति और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं।

आगे की राह:

- **शहरी परिवहन सुधार:**

- बहुविध एकीकरण अपनाएँ: उपनगरीय रेलगाड़ियाँ, मेट्रो, बसें, घाट।
- किफायती और समावेशी परिवहन में निवेश करें: बेहतर सार्वजनिक बसें, सब्सिडी वाले मेट्रो किराए।

- **शहरी लचीलापन योजना:**

- कार्य क्षेत्रों को विकेंद्रीकृत करने और व्यस्ततम घंटों में लोड कम करने के लिए शहरों को फिर से डिज़ाइन करें।
- स्टेशनों, पुलों और परिवहन नोड्स में आपदा की तैयारी को मजबूत करें।

- **सतत शहरीकरण:**

- जल परिवहन जैसे पर्यावरण के अनुकूल साधनों को बढ़ावा दें।
- भूमि-उपयोग और परिवहन योजना को एकीकृत करें।

- **शहरी राहत के रूप में ग्रामीण विकास:**

- मजबूर शहरी पलायन को कम करने के लिए कृषि को पुनर्जीवित करें और ग्रामीण रोजगार का सृजन करें।

निष्कर्ष:

- मुंब्रा ट्रेन हादसा सिर्फ़ परिवहन की विफलता नहीं है - यह भारत के शहरीकरण संकट का प्रतीक है। इसे संबोधित करने के लिए सुरक्षा सुविधाओं से ज़्यादा की ज़रूरत है; इसके लिए संरचनात्मक शहरी सुधार, समावेशी गतिशीलता और एक सतत विकास दृष्टिकोण की ज़रूरत है। जब तक मुंबई जैसे शहरों की योजना लोगों के लिए नहीं बनाई जाती, न कि सिर्फ़ बुनियादी ढांचे के लिए, तब तक ऐसी त्रासदियाँ दोहराई जाती रहेंगी।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारतीय शहरों में अनियोजित शहरीकरण के मुख्य परिणाम भीड़भाड़ और असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन हैं। मुंबई में हाल की घटनाओं के संदर्भ में जाँच करें। (250 wrds)

ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में कूटनीतिक प्रयासों के मद्देनजर, यह लेख भारत के अपने मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के दृष्टिकोण की आलोचना करता है - खास तौर पर आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर। इसमें तर्क दिया गया है कि भारत-पाकिस्तान के मुद्दों का वैश्वीकरण ऐतिहासिक रूप से भारत के हितों की पूर्ति नहीं करता है और यह रणनीतिक रूप से कमज़ोर बना हुआ है।

The hazards of going global on India-Pakistan issues

Operation Sindoor and subsequent events thereafter have, once again, highlighted the futility of bilateral and multilateral diplomacy in resolving differences between India and Pakistan. An entangled web of frozen ideas has enveloped the situation making it impossible to separate the different strands. The developments following the Second World War and the evolution of the Cold War have also impacted heavily on the situation. Thus, any initiative, however sincere and logical it may be, will be hampered by the existing literature formulated by the United Nations and other international bodies, not to speak of Pakistan's stubborn position that Kashmir is the core issue. It is for this reason that Pakistan finds the smokescreen of resolutions and concepts relating to Jammu and Kashmir (J&K), terrorism, self-determination, non-proliferation and peaceful settlement of disputes spread over the last 70 years or more.

For instance, in the briefing given to India's seven teams of special envoys sent out to various countries after Operation Sindoor, the very first point they were asked to assert was that J&K is an integral part of India. Most countries, particularly those which do not follow developments closely, would look up the literature and the UN maps and find that there is an inscription on UN maps depicting the India-Pakistan border, particularly in the region of J&K. The inscription says, "Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties." Sometimes, there is a more general disclaimer regarding boundaries on the map such as: "the boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations." Therefore, most countries would not make a commitment on the question of borders. At best, they would tell us that a bilateral solution, as envisaged in the Simla Agreement, would be desirable.

India's stand on terror

Equally complex is India's position on terrorism. More than 30 years ago, India introduced in the UN General Assembly, a draft for a Comprehensive Convention against Terrorism, which was dismissed as an anti-Pakistan move in



T.P. Sreenivasan

is a former Ambassador of India, who has specialised in multilateral diplomacy. He is the only Indian diplomat who has served at the Ambassadorial level at the United Nations in New York, Vienna and Nairobi and headed the UN Division in the Ministry of External Affairs

Several controversial concepts in the United Nations can weaken India's push to fight terror being fostered across its borders

which others were not interested. A one man department against terrorism in Vienna was nothing more than a research post. It did not even define terrorism because of the dictum that one man's terrorist is another man's freedom fighter. The support that India had given to fighters in Africa and Sri Lanka was pointed out as an example of the difficulty in defining terrorism. The only thing that the UN could do was to keep the definition of terrorism as vague as possible.

The shocking events of 9/11 (2001) brought terrorism, which was considered to be confined to West Asia and South Asia, centre stage in the United States and Europe and it appeared that decisive action would be taken to deal with the menace globally. But after hectic activity in the political and legal bodies of the UN to finalise binding laws, the focus shifted to U.S. military action in Afghanistan, which resulted in the ouster of the Taliban government. The war in Afghanistan was meant to root out terrorism, but after decades of conflict, the U.S. fled the country, leaving the Taliban in power.

The UN's approach

The UN Security Council has established several mechanisms to combat international terrorism, that are primarily centred around the various resolutions. Under these all member-states are obliged to take various economic and security measures to prevent the commission of terrorist acts. The Counter-Terrorism Committee of the Security Council was authorised to monitor the implementation of the overall plan. As for action against terrorists, this can be covered under Article 51 of the UN Charter, which recognises the inherent right of self defence if an armed attack occurs against a member-state. Though the application of this right in the case of terrorist attacks is complicated, it can provide a basis for a state to take action against terrorist groups that have attacked it. India's position about surgical strikes on terrorist infrastructure will be judged as to whether such action is proportionate and in accordance with international humanitarian law.

The Security Council's approach to counter-terrorism recognises that it requires a comprehensive "whole-of-society" approach that respects human rights and the rule of law. It emphasises international cooperation, the importance of addressing the conditions

conducive to terrorism, and the need to prevent and counter violent extremism. In these circumstances, it will be hard for India to get a clear endorsement of its actions against terrorism. India does bring up terrorist attacks to the Security Council, but the Counter Terrorism Committee has not taken a clear position on the right of nations to treat a terrorist attack as an act of war – the new doctrine advanced by India.

The ceasefire along the Line of Control (LoC) and India's restraint in crossing the LoC even in conflict situations are the other factors which are likely to come into play in any discussion in the Security Council or other international fora on India's strategic strikes. India's special envoys may have faced these questions in discussions even with friendly countries.

The issue of hyphenation

When India took the issue of Pakistan's invasion of Kashmir to the UN, it was a pure case of aggression which should have been considered under Chapter VII of the Charter. But as it happened, the issue was discussed under Article VI on Pacific Settlement of Disputes.

Consequently, several extraneous ideas were incorporated in the agenda, leading to western countries hyphenating India and Pakistan on every issue. When Pakistan and India acquired nuclear weapons, Kashmir was considered a nuclear hot spot. India has a non-first use doctrine, while Pakistan threatens to multiply its conventional military capability.

India has an established position that any bilateral discussion would only be on terrorism and the status of Pakistan Occupied Kashmir. Therefore, diplomacy at the bilateral level or multilateral level is unlikely to be effective. Pakistan will continue to internationalise the Kashmir issue, but India should refrain from seeking international intervention or support. The reports of the special envoys will indicate, if anything, that such efforts are futile, given the history of the evolution of "the India-Pakistan question" in the Security Council.

India has nothing to gain by raising its concerns internationally as its narrative has got entangled in several controversial concepts in the UN. India's only option is to ensure its security by appropriate military action as long as Pakistan continues its policy of inflicting a thousand cuts on India to gain Indian territory.

लेख से मुख्य तर्क:

- **जमे हुए कूटनीतिक ढाँचे:**

- दशकों से चले आ रहे संयुक्त राष्ट्र के संकल्प, शीत युद्ध की राजनीति और कश्मीर पर पाकिस्तान के कथन ने पुराने और पक्षपाती विचारों का एक जटिल जाल बना दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय साहित्य (जैसे संयुक्त राष्ट्र के नक्शे या नियंत्रण रेखा पर अस्वीकरण) जम्मू और कश्मीर पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं करता है।
- इसलिए, इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण केवल पुराने कूटनीतिक जाल को पुनर्जीवित करता है।

- **बहुपक्षीय मंचों की अप्रभावीता:**

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के लंबे समय से लंबित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) ने कोई प्रगति नहीं की है, मुख्य रूप से आतंकवाद की परिभाषा पर वैश्विक असहमति के कारण।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति जैसे वैश्विक आतंकवाद विरोधी तंत्र ने सर्जिकल स्ट्राइक या आतंकवाद को युद्ध की कार्रवाई कहने जैसी भारत की सक्रिय रणनीतियों का समर्थन करने से परहेज किया है।

- **पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय कूटनीति को अवरुद्ध करना:**

- पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना जारी रखता है और द्विपक्षीय वार्ता को अस्वीकार करता है जब तक कि कश्मीर केंद्रीय विषय न हो।
- दूसरी ओर, भारत शिमला समझौते के सिद्धांतों पर अड़ा हुआ है, आतंकवाद और पीओके तक ही सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप कूटनीतिक गतिरोध पैदा हो रहा है।

- **हाइफ्रनेशन समस्या:**

- भारत और पाकिस्तान को पश्चिम द्वारा एक संयुक्त चिंता (हाइफ्रनेशन) के रूप में ऐतिहासिक रूप से माना जाता रहा है - विशेष रूप से परमाणुकरण के बाद - जिसके कारण कश्मीर को "परमाणु फ्लैशपॉइंट" के रूप में देखा जाने लगा है, जो इसे घरेलू सुरक्षा मुद्दे के रूप में पेश करने के भारत के प्रयासों को कमजोर करता है।

- **संयुक्त राष्ट्र की संरचनात्मक बाधाएँ:**

- संयुक्त राष्ट्र निकाय अक्सर संतुलित या अस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे भारत के लिए अपने क्षेत्रीय दावों या आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के लिए स्पष्ट समर्थन प्राप्त करना असंभव हो जाता है।
- **1947** में पाकिस्तान के आक्रमण के लिए अध्याय **VII** के तहत कार्रवाई की कमी ने एक मिसाल कायम की है जो वर्तमान कूटनीति को परेशान करती है।

भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ:

- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सीमाएँ:**

- पाकिस्तान के साथ अपने संघर्ष को वैश्वीकृत करके भारत को कोई निर्णायक लाभ नहीं मिलता है।

- संयुक्त राष्ट्र का तटस्थ रुख और प्रक्रियागत सीमाएं अक्सर कूटनीतिक समर्थन पाने के भारत के प्रयासों को विफल कर देती हैं।
- **आत्मनिर्भर रणनीति की आवश्यकता:**
 - जब तक पाकिस्तान अपनी "हजारों कटों की नीति" पर चलता रहेगा, तब तक भारत के लिए सबसे अच्छा उपाय अंतरराष्ट्रीय अपीलों के बजाय, सैन्य और रणनीतिक कार्रवाइयों के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।
- **कूटनीति को फिर से परिभाषित करना:**
 - भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय जुड़ावों, खासकर पश्चिमी शक्तियों के साथ, को भारत-पाकिस्तान द्विआधारी से अलग करना चाहिए और खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में पेश करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष:

- भारत को संरचनात्मक रूप से विवश और ऐतिहासिक रूप से पक्षपाती अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अत्यधिक निर्भरता से बचकर पाकिस्तान के संबंध में अपनी कूटनीतिक रणनीति को फिर से बदलना चाहिए। भारत-पाकिस्तान संघर्ष, खासकर कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर, रणनीतिक और द्विपक्षीय रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, जिसमें घरेलू क्षमता निर्माण और निरोध तंत्र केंद्रीय भूमिका निभाएं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के भारत के प्रयासों को बहुपक्षीय मंचों पर अक्सर संरचनात्मक और कूटनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा है। भारत-पाकिस्तान संघर्षों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करें। (250 wrds)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) ने हाल ही में भारत के वित्तीय क्षेत्र की साइबर लचीलापन का आकलन करने और अनुपालन को आसान बनाने तथा दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों को वापस करने के लिए सुधारों की खोज करने के लिए एक बैठक आयोजित की। इन उपायों को वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, दक्षता और समावेशिता को मजबूत करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

FSDC looks to enhance cybersecurity, ease compliance burden

The Hindu Bureau

NEW DELHI

The Financial Stability and Development Council (FSDC) chaired by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, on Tuesday examined various ways to enhance the cyber resilience framework of the financial sector and ease the compliance burden.

“In light of the analysis of cybersecurity regulations, sectoral preparedness, and the recommendations of Financial Sector Assessment Programme (FSAP) 2024-25, the FSDC considered strengthening

the cyber resilience framework of the Indian financial sector through a financial sector-specific cybersecurity strategy,” the Finance Ministry said.

The FSDC also looked into ways to implement past decisions, such as reducing the amount of unclaimed assets in the financial sector, and seamless refund of such assets to the rightful owners.

The FSDC also discussed prescribing common know-your-customer (KYC) norms and simplify the process, including for NRIs, in the Indian securities market.

मुख्य बातें:

- **वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा:**

- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (**FSAP**) **2024-25** की सिफारिशों के मद्देनजर, **FSDC** ने एक क्षेत्र-विशिष्ट साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू करने पर चर्चा की।
- इसका उद्देश्य साइबर लचीलापन में सुधार करना है, खासकर बढ़ते डिजिटल लेनदेन, फिनटेक विकास और साइबर खतरों के जोखिम को देखते हुए।
- यह कदम उपभोक्ता विश्वास और वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइबर हमले संस्थानों और बाजारों को अस्थिर कर सकते हैं।

- **अनुपालन और केवाईसी मानदंडों को सरल बनाना:**

- परिषद ने आम केवाईसी मानदंडों की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय प्रतिभूति बाजार तक अधिक सुचारू रूप से पहुंचने में मदद करने के लिए।
- एक सुव्यवस्थित और एकीकृत केवाईसी प्रक्रिया दोहराव को कम कर सकती है, नियामक दक्षता में सुधार कर सकती है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है।

- **वित्तीय क्षेत्र में दावा न की गई संपत्तियाँ:**

- निष्क्रिय बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में बड़ी मात्रा में दावा न किया गया धन है।
- **FSDC** ने सही मालिकों को निर्बाध रिफंड के लिए तंत्र पर जोर दिया, जिसके लिए अंतर-एजेंसी समन्वय और तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन के लिए निहितार्थ:

- **साइबर शासन को मजबूत करना:**

- एक समर्पित वित्तीय साइबर सुरक्षा रणनीति भारत की डिजिटल कमजोरियों की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है।
- यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित है और विशेष रूप से बढ़ते डिजिटल अपनाने के बीच नियामक निरीक्षण को बढ़ाता है।

- **वित्त में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना:**

- सामान्य **KYC** मानदंड संस्थानों के लिए अनुपालन थकान को कम करते हैं और निवेशक अनुभव को बेहतर बनाते हैं, खासकर पूंजी बाजारों और सीमा पार लेनदेन में।

- **सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही को संबोधित करना:**

- बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को वापस करना नागरिक-केंद्रित शासन दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में विश्वास बढ़ाता है।

निष्कर्ष:

- साइबर लचीलापन, अनुपालन सरलीकरण और संपत्ति वसूली पर **FSDC** का ध्यान एक सक्रिय और सुधार-उन्मुख वित्तीय शासन एजेंडे का संकेत देता है। ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि भारत की वित्तीय प्रणाली सुरक्षित, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनी रहे, विशेष रूप से तब जब डिजिटल वित्त का विस्तार जारी है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के बढ़ते डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर सुरक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चुनौतियों पर चर्चा करें और भारतीय वित्तीय क्षेत्र में साइबर लचीलापन मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। (250 wrds)

Page : 08 Editorial Analysis

India's legal bridge is one of reciprocity, not roadblocks

In May this year, the Bar Council of India (BCI) implemented the Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India (hereinafter 'rules'). While many within the legal profession lauded the rules, a few law firms based in the United States have voiced strong objections, calling the rules a "non-trade barrier" and a "deliberate move to exclude or freeze out" U.S. law firms from engaging with the Indian legal ecosystem.

However, such criticism reflects a limited appreciation of the statutory mandate of the BCI and an inadequate understanding of India's comprehensive regulatory framework governing its legal affairs. On the contrary, the rules strike a balance by facilitating the entry of foreign practitioners and firms while upholding professional standards and safeguarding the interests of stakeholders within the Indian legal profession.

The criticism

First, it is contended that the rules create a 'non-tariff trade barrier' by imposing procedural restrictions on U.S.-based law firms and legal professionals, thereby attempting to 'freeze out' their entry into the Indian legal landscape. Second, it is alleged that the interests of the U.S. were overlooked during global consultations preceding the framing of the rules, making it difficult for U.S. law firms and professionals to comply with the stipulated mandates. Third, the requirement to disclose details such as the 'nature of legal work' and 'client identity' is said to conflict with the American Bar Association (ABA) Model Rules on client confidentiality. Fourth, the regulations governing fly-in, fly-out provisions have been criticised for being inconsistent with the principle of reciprocity, as they impose duration-based, disclosure-based restrictions not similarly applied to Indian counterparts operating in the U.S. Fifth, the



Shivang Tripathi

is a Senior Research Fellow at the Faculty of Law, Banaras Hindu University, Varanasi



Shaiwal Satyarthi

is a Professor at the Faculty of Law, University of Delhi

Criticism of the 'Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India' is unfair

contention is that the rules have been introduced as a surprise move, providing no transition period for adjustment, thereby placing U.S. firms and professionals at a disadvantage. Finally, it is argued that the rules could adversely impact U.S.-India bilateral trade and legal engagement, as they may discourage Indian corporations from undertaking transactions involving U.S. laws, owing to a dearth of legal professionals who are skilled in U.S. laws.

A reality check

First, the BCI is not a trade body, but a statutory body to maintain standards of professional conduct and safeguard the interests of legal professionals across India. Second, constitutionally and technically, the practice of law cannot form part of a trade agreement, as it is governed under Entries 77 and 78 of the Union List, unlike entries dealing with trade and commerce under the Seventh Schedule of the Constitution of India. Second, In *Bar of Indian Lawyers Through Its President Jasbir Singh Malik vs D.K. Gandhi* (2024), it was held that it was a contract of personal service, thereby segregating it from trade and business practices. Third, India recently chose not to include legal services in the United Kingdom-India Free Trade Agreement, despite facing significant international pressure. This reflects India's consistent position that legal services require a distinct regulatory framework.

Fourth, the impugned rules do not bar foreign law firms and practitioners but liberalise the Indian legal ecosystem, albeit in a structured and regulated manner. For instance, Rules 3 and 4 permit foreign law firms to operate in India, subject to registration and compliance with ethical and professional conditions. Further, the fly-in, fly-out model, under the proviso to rule 3(1), allows temporary visits, subject to an aggregate stay not exceeding 60 days within a 12-month period. Fifth, Indian legal professionals lack universal access to the U.S. legal system and

are subjected to rigorous, state-specific, examination-based licensing regimes. The reciprocity requirement under the rules, subjecting the U.S. counterparts to similar regulatory compliances, merely establishes equivalence. Sixth, rule 4(h), which mandates a certificate of 'good standing at the bar', has been flagged by U.S. stakeholders as problematic, owing to its decentralised ecosystem. However, this limitation stems from the U.S. regulatory structure and cannot be attributed to the BCI or India.

Notably, rule 6 of chapter III allows for flexibility, empowering the BCI to verify such credentials holistically and on a case-by-case basis, thereby ensuring an accommodating approach, subject to an adherence to basic ethical and professional standards. Seventh, the requirement to disclose the nature and the extent of legal work does not dilute client confidentiality, as the objective is to obtain general information about the legal work or transaction. This ensures that the activities of foreign legal professionals remain within the permitted contours of legal practice in India.

There has been debate and discussion

Finally, the criticism regarding lack of consultations or a transition period before the operationalisation of the rules holds no ground. Debates and discussion have been ongoing for over two decades, encompassing expert committee reports, global consultations, and key judicial decisions such as *Lawyers Collective vs Bar Council of India* (2009) and *Bar Council of India vs A.K. Balaji* (2018) which have collectively laid the foundation for the present regulatory framework.

Far from being a barrier, the rules aim to create a cooperative bridge liberalising the Indian legal landscape in a measured manner, while safeguarding professional integrity, client confidentiality, and upholding the vital principles of reciprocity and ethical accountability.

Paper 02 : शासन

UPSC Mains Practice Question : भारत में विदेशी कानून फर्मों के विनियमन में पेशेवर नैतिकता, राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक कानूनी जुड़ाव के बीच संतुलन होना चाहिए। इस संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाल के नियमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (250 words)

संदर्भ:

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने हाल ही में भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम (2024) लागू किए हैं। इसने बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से कुछ अमेरिकी-आधारित लॉ फर्मों की आलोचना ने दावा किया है कि ये नियम व्यापार बाधाएं पैदा करते हैं। हालाँकि, लेख में तर्क दिया गया है कि ये नियम भारत के संप्रभु कानूनी जनादेश को दर्शाते हैं, जो व्यापार उदारीकरण पर नहीं बल्कि पेशेवर विनियमन पर आधारित हैं।

मुख्य मुद्दे और स्पष्टीकरण:

- **यू.एस. लॉ फर्मों द्वारा आलोचना:**

- गैर-टैरिफ व्यापार अवरोध के आरोप जो विदेशी लॉ फर्मों को बाहर करते हैं।
- क्लाइंट गोपनीयता और **ABA** मॉडल नियमों के अनुपालन पर चिंताएँ।
- संक्रमण समय की कमी और पारस्परिक असंतुलन के दावे।
- डर है कि यह भारत-यू.एस. कानूनी और वाणिज्यिक जुड़ाव को प्रभावित कर सकता है।

- **कानूनी और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:**

- भारत में कानून का अभ्यास एक विनियमित पेशा है, न कि वाणिज्यिक व्यापार।
- भारतीय संविधान (प्रविष्टियाँ **77** और **78**, संघ सूची) के अनुसार, कानून व्यापार के विपरीत शासन के अंतर्गत आता है।
- भारतीय न्यायालयों (जैसे, बार ऑफ़ इंडियन लॉयर्स बनाम डी.के. गांधी) ने कानून को व्यापार और व्यवसाय से स्पष्ट रूप से अलग किया है।

- **पारस्परिकता और विनियमन:**

- भारतीय वकीलों को अमेरिका में सख्त लाइसेंसिंग का सामना करना पड़ता है; भारत इन नियमों के माध्यम से समान अनुपालन की अपेक्षा करता है।
- नियम **3** और **4** जैसे प्रावधान विदेशी फर्मों को नियंत्रित उदारीकरण सुनिश्चित करते हुए पंजीकरण और संचालन करने की अनुमति देते हैं।
- **60-दिवसीय फ्लॉयड-इन-फ्लॉयड-आउट क्लॉज** पूर्णकालिक अभ्यास के बिना अस्थायी सलाहकार भूमिकाओं की सुविधा प्रदान करता है।

- **नैतिक मानकों को बनाए रखना:**

- अच्छी स्थिति के प्रमाण पत्र जैसी आवश्यकताएँ उचित हैं, भले ही अमेरिकी संदर्भ में चुनौतीपूर्ण हों।
- नियम 6 बीसीआई को विवेक का उपयोग करने और ऐसे मामलों का समग्र रूप से आकलन करने की अनुमति देता है।
- ग्राहकों का खुलासा किए बिना कानूनी कार्य के प्रकार का खुलासा गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करता है।

- **दीर्घकालिक परामर्श और न्यायिक समर्थन:**

- यह कदम अचानक नहीं उठाया गया है। यह दो दशकों के नीतिगत विचार-विमर्श, समिति की रिपोर्ट और निर्णयों (वकील सामूहिक, ए.के. बालाजी मामले) का परिणाम है।
- भारतीय कानूनी संप्रभुता और पेशेवर मानदंडों के साथ संरेखित, मापा कानूनी उदारीकरण को दर्शाता है।

भारत के कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निहितार्थ:

- **सकारात्मक परिणाम:**

- भारत के कानूनी पेशे के संरचित वैश्विक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- घरेलू कानूनी बाजार, विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों को अनियंत्रित विदेशी प्रभुत्व से बचाता है।
- वैश्विक कानूनी जुड़ाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए पारस्परिकता को बनाए रखता है।

- **चुनौतियाँ:**

- भारत की कानूनी संरचना के कारण विदेशी फर्मों के लिए प्रशासनिक जटिलताएँ।
- अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या सीमा पार विलय जैसे क्षेत्रों में कानूनी सहयोग में संभावित मंदी।
- भारत की कानूनी सेवाओं तक खुली पहुँच की माँग करने वाले देशों के साथ कूटनीतिक घर्षण।

निष्कर्ष:

- बीसीआई नियम कोई बाधा नहीं, बल्कि एक पुल हैं - जो विनियमित, नैतिक और पारस्परिक शर्तों के तहत भारत में विदेशी कानूनी भागीदारी को सक्षम बनाते हैं। भारत के लिए, कानूनी अभ्यास एक व्यापार योग्य वस्तु नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित, संवैधानिक सिद्धांतों और संप्रभुता द्वारा शासित एक पेशेवर सेवा है। यह कदम पेशेवर मानकों या राष्ट्रीय कानूनी अखंडता से समझौता किए बिना वैश्विक एकीकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।